



TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

Vol./Year-10 Issue - 27

Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad
केन्द्र एवं उ०प्र० सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

www.tbcgzb.com

News
of the
Week

उच्चतम न्यायालय ने साल 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों को तुरंत मौत की सजा देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

Inside
Ghaziabad

पेज नंबर 2
रैपिड रेल कॉरिडोर में चार स्टेशनों के बदलेंगे...

पेज नंबर 5
Broker found dead near Crossings police outpost



लोन घोटाले में गारंटर को कोर्ट ने भेजा जेल

गाजियाबाद : लोन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने बैंक गारंटर को जेल भेज दिया। आरोपित ने कोर्ट में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मामला नोएडा के सेक्टर 27 स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है। वर्ष 2013 में इस बैंक से करीब नौ करोड़ का कारोबारी लोन घोटाला हुआ था। कविनगर के रहने वाले कारोबारी अश्वनी चानना और गिरीश चानना ने नोएडा के बैंक से नौ करोड़ का लोन लिया था।

18 दिसंबर को लगेगा पशु आरोग्य मेला

गाजियाबाद : 18 दिसंबर को लोनी में पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। बीमार, बांझपन समेत अन्य रोगों का इस मेले में पशु चिकित्सकों के द्वारा इलाज कराया जाएगा। पशुपालन विभाग इन दोनों मेलों की तैयारियों में लगा हुआ है। वे सभी पशुपालक जिनके पशुओं को टीकाकरण नहीं हुआ है, वे भी इस मेले में आकर अपने पशुओं को टीका लगवा सकते हैं।

खोड़ा में मीट की दो अवैध दुकान सील

गाजियाबाद : खोड़ा में अवैध रूप से चल रही मीट की दो दुकानों को प्रशासन ने मंगलवार को सील कर दिया। यह दुकाने बिना लाइसेंस और मानकों के विपरीत चल रही थीं। एसडीएम सदर विवेक मिश्र ने बताया कि मंगलवार को उनके नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष सिंह, थाना प्रभारी खोड़ा धर्मेन्द्र सिंह व नगर पालिका की टीम को साथ लेकर खोड़ा का निरीक्षण किया गया।

इंदिरापुरम गैलोर ने किया स्लम एरिया में भोजन और कपड़ों का वितरण

रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने आर्थिक और सामुदायिक विकास के अंतर्गत की सेवा

गाजियाबाद : रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने शनिवार को वसुंधरा के स्लम एरिया में कपड़े व भोजन का वितरण किया। कपड़े पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। क्लब की टीम सर्वप्रथम वसुंधरा सेक्टर-तीन स्थित झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे लोगों के पास पहुंची। भोजन व कपड़े देखकर यहां काफी संख्या में झुग्गी झोपड़ी के लोग एकत्र हो गए। इस दौरान सभी को भोजन खिलाया गया तथा कपड़े बांटे गए। सर्दी में कपड़े मिलने से सभी काफी खुश हो गए। यहां कई बच्चे ऐसे मिले जिनके बदन पर इस कड़कड़ाती सर्दी में कपड़े तक नहीं थे। इसके बाद टीम वसुंधरा सेक्टर-10 स्थित स्लम एरिया में पहुंची और यहां भी कपड़े व भोजन बांटा। यहां भी सैकड़ों जरूरतमंदों को कपड़े बांटे गए। चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव ने



बताया कि क्लब द्वारा हर वर्ष कपड़े व भोजन का वितरण किया जाता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, फुटपाथ व स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को सर्दी से बचाने के लिए

समय-समय पर कंबल भी बांटे जाते हैं। वहीं कुनिका भार्गव ने कहा कि जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना ही मानव धर्म है। भोजन व कपड़े वितरण में चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव, पूर्व अध

यक्ष मनीषा भार्गव, प्रतीक भार्गव, कुनिका भार्गव, पूनम बाला, संजय शर्मा व विक्रम आदि ने सहयोग किया।

संबंधित फोटो पेज 8 पर

केडीपी बिल्डर का गेट व ऑफिस को प्रशासन ने किया गया सील

गाजियाबाद : बकाया स्टॉप पर प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए केडीपी बिल्डर के ऑफिस व गेट समेत सात की संपत्ति पर सील लगा दी। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर 13 लोगों के व विद्युत कनेक्शन काटे गए। मंगलवार को कुल 23 मामलों में कार्यवाही की गई। इसकी एवज में प्रशासन ने मंगलवार को 37.10 लाख रुपये राजस्व की वसूली की। एसडीएम सदर विवेक कुमार मिश्र ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन में केडीपी बिल्डर ग्रुप के मनोज गोयल पर 5.50 करोड़ रुपये का स्टॉप बकाया था। इसके चलते

उनकी आरसी जारी की गई थी। इसके बावजूद भी बकाया स्टॉप शुल्क जमा नहीं किया जा रहा था। इस पर मंगलवार को नायब तहसीलदार व अमीन की टीम भेजकर केडीपी बिल्डर का ऑफिस व गेट पर सील लगवा दी गई। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही साहिबाबाद के डीएलएफ स्थित प्रीति पत्नी विकास का 50 हजार रुपये विद्युत बिल बकाया होने पर फ्लैट सील किया गया। डीएलएफ में ही 40 हजार का विद्युत बिल बकाया होने पर संजय कंसल का फ्लैट सील किया गया।

Cricket stadium on track, funds won't queer pitch

GHAZIABAD: The UP Cricket Association (UPCA) on Thursday agreed to Ghaziabad Development Authority's (GDA) demand for funds to build India's largest international cricket stadium in the city. This comes two days after TBC reported that the stadium proposal had stalled due to a funds stalemate between the cricket body and GDA. According to the understanding, the association will mortgage a portion of the stadium's land, worth Rs 7.5 crore, following which GDA

will approve the map. Work on the stadium is expected to start by January 15, officials said. Another bone of contention was floor area ratio (FAR). The association has been demanding enhanced FAR on which the development authority has been dragging its feet. "After CAG raised objection to GDA not charging Rs 7.5 crore acquisition fee from UPCA, we had to keep the stadium's map approval in abeyance," said Kanchan Verma, vice-chairperson, GDA.

रैपिड रेल कॉरिडोर में चार स्टेशनों के बदलेंगे एंट्री व एग्जिट प्वाइंट

गाजियाबाद : दिल्ली सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट के गाजियाबाद में पड़ने वाले चार स्टेशनों के प्रवेश और निकास बिंदु में परिवर्तन किया जा सकता है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने चारों स्टेशनों के एंट्री व एग्जिट प्वाइंट में बदलाव के लिए जीडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। एनसीआरटीसी के मुताबिक स्टेशनों के प्रवेश व निकास बिंदु में परिवर्तन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। रैपिड रेल का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले दिल्ली-मेरठ हाइवे पर



गाजियाबाद के मेरठ तिराहे से लेकर दुहाई तक सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। निर्माण करने पर एनसीआरटीसी की डिजाइनर टीम की ओर से लोगों की सुविधा के लिहाज से स्टेशनों के डिजाइन व लेआउट में परिवर्तन पर मंथन किया जा रहा है। इसके तहत चार स्टेशनों के ले-आउट में कुछ बदलाव के लिए जीडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी से

इन चार स्टेशनों के बदलेंगे प्रवेश व निकास बिंदु
गुलधर स्टेशन, मुरादनगर, मोदीनगर नार्थ और मोदीनगर साउथ के प्रवेश व निकास बिंदु में परिवर्तन किया जाना है। सराय काले खां से मेरठ मोदीपुरम कॉरिडोर पर कुल 24 स्टेशन है।

अनुमति मांगी गई है। जीडीए मुख्य अभियंता विवेकानंद सिंह का कहना है कि एनसीआरटीसी ने रैपिड रेल के चार प्रोजेक्ट के एंट्री व एग्जिट प्वाइंट में बदलाव के लिए प्राधिकरण से एनओसी की मांग की है। स्टेशनों का ले-आउट देखने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रोड के कॉरिडोर की पहले लंबाई 92 किलो मीटर थी। इसमें से

मेरठ में एक स्टेशन कम किए जाने से कॉरिडोर की लंबाई घटकर 82 किमी रह गई है। कॉरिडोर पर 55 मिनट में सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक पहुंचा जा सकेगा। प्रोजेक्ट का कुल बजट 32,598 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट में यूपी सरकार 4300 करोड़, दिल्ली सरकार 861 करोड़ और केंद्र सरकार 5165 करोड़ रुपये अंशदान देगी।

19 व 20 दिसंबर को जिले में आयोजित होगा रंगोत्सव कार्यक्रम

गाजियाबाद : जिले में 19 व 20 दिसंबर को आयोजित होने वाले रंगोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी ने कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा व्यवसायिक कलाकारों, स्कूली शिक्षकों, ललित कला अकादमी छात्र-छात्राएं, विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थाओं, कला विभाग समेत अन्य व्यक्ति जो चित्रकला में रुचि रखता है कि लिए यह रंगोत्सव प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। उन्होंने बैठक में बताया कि इस प्रतियोगिता का विषय समाज में व्याप्त बुराईयों के उन्मूलन से संबंधित है।

जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश

गाजियाबाद : छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी को लंबे समय बाद मिली बंपर जीत से कांग्रेसी गदगद हैं। पूर्व मंत्री सतीश शर्मा के आवास के अलावा जिला एवं महानगर कार्यालय पर जीत का जमकर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा होंगे। इस मौके पर संजीव शर्मा, पवन शर्मा, जाकिर सैफी, सुनील चौधरी, सुभाष शर्मा, पूजा चड्ढा, आसिफ सैफी, नसीम खान, मांगेराम त्यागी, अहसान अली, पूजा चड्ढा आदि मौजूद रहे। उधर, महानगर अध



यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने इस जीत से उत्साहित होते हुए कहा कि यह बदलाव का युग है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय है। तीन राज्यों में कांग्रेस के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर जिला कांग्रेस कार्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी

और ढोल नगाड़े पर डांस करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। जिला अध्यक्ष हरेंद्र कसाना ने कहा नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार देश में जीएसटी नोटबंदी कर लोगों को परेशान किया उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है।

सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका

गाजियाबाद : नोएडा प्राधिकरण घोटाले व आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित कुसुम लता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश आने तक कुसुम लता से संबंधित मामलों की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में नहीं होगी। मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई के लिए कुसुम लता, यादव सिंह सहित अन्य आरोपी विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। आरोपित के अधिवक्ता ने अदालत को सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक सुनवाई पर रोक लगा दी है।

20 दिसंबर तक वेस्ट मैनेजमेंट की तैयारियां करें पूरी : डीपीआरओ

गाजियाबाद : जिले के 68 ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों की विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिसमें इन ग्राम पंचायतों में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सही ढंग से बनवाने संबंधी जरूरी निर्देश दिए। वहीं 20 दिसंबर तक सारी तैयारी पूरी करने को कहा गया। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन 68 ग्राम पंचायतों में ही पहले बनना है। बैठक में डीपीआरओ रेनु शीवास्तव ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट को चालू करने की तैयारियों को 20 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। ई रिक्शा और अन्य स्रोत से कचरे को एकत्रित करें। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जैविक कूड़ा अलग किया जाएगा।

कई स्कूल नहीं दे रहे हैं टीकाकरण के लिए तारीख

गाजियाबाद : मीजिल्स और रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए चलाया जा रहा एमआर टीकाकरण अभियान पूरे दिसंबर स्कूलों में चलाया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कई स्कूलों ने टीकाकरण के लिए हामी भर दी है लेकिन टीकाकरण के लिए तारीख स्कूलों से नहीं मिल पा रही है। इस वजह से स्कूलों में अभियान को दिसंबर भर चलाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि एमआर टीकाकरण अभियान के तहत नौ माह से 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। पांच सप्ताह तक चलने वाले अभियान को स्कूलों में शुरुआत

के दो सप्ताह चलाया जाना था। लगभग दो सप्ताह इसे पूरे हो चुके हैं। तय लक्ष्य के मुताबिक 3500 स्कूलों में छात्रों का टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग को करना है। इसमें से करीब 2500 स्कूलों में साढ़े चार लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण जिले में कर दिया गया है। अभी स्वास्थ्य विभाग के समक्ष कई स्कूल परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनमें पब्लिक स्कूल सबसे अधिक हैं। स्कूलों ने टीकाकरण के लिए हामी भी भर दी है लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण के लिए तारीख और समय स्कूलों से नहीं मिल रहा है।

बिल्डर ने तोड़ी सील, मुकदमा दर्ज

गाजियाबाद : जीडीए द्वारा सील किए गए फ्लैटों की सील तोड़ने के आरोप में जीडीए द्वारा दो बिल्डरों मुकेश त्यागी और हरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जीडीए प्रवर्तन जोन-3 के सहायक अभियंता आरबी सिंह ने बताया कि मुकेश त्यागी और हरेंद्र ने गोविंदपुरम के शताब्दीपुरम में सिग्नेचर टावर बनाया था। यह भवन पूरी तरह से अवैध था, जिसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया। कई बार नोटिस के बाद भी जवाब नहीं मिला तो जीडीए ने भवन में बने 28 में से 10 फ्लैटों पर सील लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक 18 फ्लैटों में परिवार रहने लगे थे।

लोन करा फ्लैट और बिल्डिंग कई बार बेच दिए, 11 के खिलाफ मुकदमा

गाजियाबाद : प्लॉट पर तीन मंजिला इमारत बना लोन कराने और फिर अलग-अलग फ्लैट बेचकर दोबारा पूरी बिल्डिंग बेच देने के मामले में कविनगर थाने में बिल्डर समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों ने बिल्डर, उसके रिश्तेदार और बैंककर्मी शामिल हैं। कविनगर थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वर्णजयंतीपुरम में ई ब्लॉक रहने वाले व्यापारी वेद प्रकाश सिंघल ने बताया कि छह फरवरी 2012 को उन्होंने मंजू जे होम्स के प्रमोटर विजयंत जैन से ई ब्लॉक में भूतल पर बना 66 वर्गमीटर का फ्लैट

14.50 लाख रुपये में खरीदा था। आरोप है कि यह फ्लैट 160 मीटर का दिखाकर उन्होंने 2009 में रिश्तेदार अल्का जैन को बेच दिया था। यूनियन बैंक आफ इंडिया के मैनेजर ने मिलीभगत से 5.20 लाख रुपये का लोन भी कर दिया। एक साल पूर्व अखबार में उन्होंने अपने ही फ्लैट की नीलामी की सूचना देखी, जिसके बाद ठगी का पता चला। आरोप लगाया कि विजयंत जैन ने पहले तीनों मंजिलों के फ्लैट अपने रिश्तेदारों को बेचे और फिर उन पर लोन करा दुबारा बेच दिया। आरोपित ने दिल्ली के एक युवक को 200 गज के प्लॉट को बिल्डिंग समेत 90 लाख रुपये में बेच दिया।

प्राधिकरण की बड़ी संपत्तियों की अब होगी ऑनलाइन नीलामी

गाजियाबाद : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की संपत्तियां खरीदने के लिए अब लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्राधिकरण के 2000 वर्ग मीटर से बड़े ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक सहित अन्य व्यावसायिक भूखंडों की अब ऑनलाइन नीलामी होगी। इस सुविधा के लागू होने पर देश के किसी भी कोने से जीडीए की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ऑनलाइन नीलामी के लिए जीडीए ने भारत सरकार की स्टील मिनिस्ट्री के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन (एमएसटीसी) के साथ करार किया है। नई व्यवस्था के तहत 20 दिसंबर से 2000 वर्गमीटर से बड़े 40 भूखंडों की ऑनलाइन नीलामी होगी। एमएसटीसी की



वेबसाइट www.mstcindia-co-in पर जाकर नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए जीडीए की वेबसाइट से भी लिंक दिया जाएगा। आवेदकों को अपनी लॉग इन प्रोफाइल आईडी बनाने के साथ सभी जानकारी व उससे संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आईडी बनने के बाद आवेदक को संबंधित निविदा प्रक्रिया की रिजर्व प्राइस से अधिक राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी। जिसकी बिड सबसे

नीलामी से बाहर तो ऑनलाइन पैसा होगा रिफंड

ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में बिड कम रहने के कारण कोई बाहर हो जाता है, तो प्राधिकरण में जमा कराई गई रिजर्व प्राइस राशि व्यक्ति के अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। अपना पैसा पाने के लिए लोगों को चक्कर नहीं काटने होंगे।

अधिक होगी, उसकी टेक्निकल व फाइनेंशियल बिड में टेक्निकल कमेटी के निर्णय के बाद अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। इससे नीलामी में पारदर्शिता रहेगी। जीडीए उपाध्यक्ष की मानें तो पूरी प्रक्रिया को 10 से 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। जीडीए वीसी कंचन वर्मा का कहना है कि प्राधिकरण के बड़े भूखंड की नीलामी अब ऑनलाइन होगी। इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी को जिम्मा दिया गया है। प्रक्रिया को 20 दिसंबर से

शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल होने वालों को ऑनलाइन ही पहले संपत्ति से जुड़ी विस्तृत जानकारी हासिल होगी। इसके लिए नीलामी वाले भूखंड की फोटो के साथ साइट का गूगल लिंक उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। अगर कोई संपत्ति को देखना चाहता है, तो उसे उस स्थान की लोकेशन उपलब्ध हो सकेगी। उसे संपत्ति की जगह की जानकारी के लिए जीडीए के चक्कर भी नहीं काटने होंगे।

जीडीए स्कीम के लिए आवेदकों की नहीं लगेंगी लाइन

गाजियाबाद : जीडीए ने अपनी स्कीम को ऑनलाइन करने का फैसला लेने के साथ ही आवेदकों की परेशानी भी कम करने का फैसला लिया है। इसके बाद आवेदकों को लंबी लाइन में लगकर फॉर्म जमा कराने, बैंक की लाइन में लगने से छुटकारा मिलेगा। वहीं, मंगलवार में रजिस्ट्री, म्यूटेशन व फ्री होल्ड कराने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू हो गई। इस संबंध में जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि जीडीए की तमाम ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवेदकों को जनहित डॉट यूपीडीए डॉट इन की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा।

इंदिरापुरम को नगर निगम के हवाले करने की प्रक्रिया शुरू

गाजियाबाद : जीडीए ने बड़ी योजना इंदिरापुरम को नगर निगम को सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में जीडीए और निगम की टीम ने इंदिरापुरम पहुंचकर संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। जीडीए पहले चरण में निगम को सड़क, स्ट्रीट लाइट और सफाई का कार्य सौंपेगा। मंगलवार को जीडीए ने निगम को योजना का मानचित्र भी सौंपा। प्राधिकरण के मुख्य अभियंता वीएन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम अब इस मानचित्र के हिसाब से सर्वे करेगा। सर्वे के बाद वह प्राधिकरण को बताएगा कि योजना में सड़क, स्ट्रीट लाइट व बिजली का कहां क्या काम बाकी है।

डेढ़ माह में खुलेगा रेरा ई-कोर्ट, आपसी समाधान को बनेगा मध्यस्थता फोरम

गाजियाबाद : बिल्डरों के आवासीय प्रोजेक्ट्स में लोगों की बगैर जुर्माने के प्रावधान वाली शिकायतों का अब ई-कोर्ट के जरिए समाधान हो जाएगा। डेढ़ माह के अंदर तैयार होने वाली ई-कोर्ट के मोबाइल एप, वेबसाइट और खास लिंक के जरिए लोग बिल्डर्स से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों निवारण का स्टेट्स भी मोबाइल एप व अन्य माध्यमों से जांचा जा सकेगा। हिंदी भवन में यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की विशेष कार्यशाला में रेरा सचिव अबरार अहमद ने कहीं। उन्होंने साफ कहा कि रेरा का गठन खासतौर पर आवंटियों की शिकायतों के समाधान के लिए हुआ है। इसलिए बायर्स की पहले सुनी जाएगी। बिल्डर्स अपील से



पहले एक बार जरूर सोच लें। कार्यशाला में आवंटियों के साथ बिल्डरों, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और जीडीए के अधिकारियों के सवाल व शंकाओं का रेरा सचिव ने समाधान किया। रेरा सचिव ने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश में बिल्डरों व बायर्स के बीच मसलों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए प्रदेश स्तर पर 18 मध्यस्थता फोरम का गठन होगा। फोरम में बायर्स के 5, बिल्डर्स के 5 प्रतिनिधियों के साथ जीडीए के अधिकारी शामिल होंगे। इनमें पांच फोरम ग्रेटर नोएडा व

31 तक पंजीकरण नहीं तो जुर्माना व जेल

रेरा की ओर से बिल्डरों को 31 दिसंबर 2018 तक पंजीकरण का मौका दिया गया है। पंजीकरण के साथ पहले के रजिस्ट्रेशन में संशोधन के लिए भी 31 तक का वक्त है। इसके बाद भी पंजीकरण नहीं कराने वालों को अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10 फीसदी जुर्माना देना होगा। इसके बाद 45 दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर फिर 10 फीसदी जुर्माना व तीन साल तक की जेल का प्रावधान है।

लखनऊ, बाकी अन्य स्थानों पर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर बिल्डर किसी भी सोसाइटी के ले-आउट में परिवर्तन करता है तो उसे दो तिहाई आवंटियों की मंजूरी लेनी होगी। प्रदेश में वर्तमान में 2000 एजेंट ही रेरा में पंजीकृत हैं। गैर पंजीकृत एजेंटों को बुकिंग का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि रेरा में आई 9000 में से दिसंबर तक 2500

शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। रेरा के ई-पैनल में तीन रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की जाएगी। इनकी तैनाती लखनऊ व ग्रेटर नोएडा में होगी। बिल्डरों को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर तीन माह में सबमिट करनी होगी। रेरा सचिव ने कहा कि रेरा में पंजीकरण के बाद बिल्डरों की स्कूटनी का जिम्मा प्राधिकरणों पर होगा।

कंप्लीशन सर्टिफिकेट में बिल्डर नहीं कर सकेंगे खेल

गाजियाबाद : कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम पर अब बिल्डर खेल नहीं कर सकेंगे। महीनों लटकाने और खर्च बढ़ाने की जुगत नहीं चलेगी। जीडीए हाउसिंग सोसायटीज को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया आसान करने जा रहा है। सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के दौरान बिल्डर को 15 एनओसी एकसाथ जमा करनी होंगी। इसके बाद 15 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। शुरुआत में 12 बड़े प्रोजेक्ट में फ्लैट पर कब्जे का इंतजार कर रहे करीब 4700 आवंटियों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। महानगर के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में कंप्लीशन सर्टिफिकेट न मिल पाने के कारण फ्लैट पर आवंटियों को कब्जा नहीं मिल रहा है। बिल्डर प्राधिकरण पर कंप्लीशन

आवासीय प्रोजेक्ट में ये एनओसी जरूरी

जीडीए से एप्रूव्ड ग्रुप हाउसिंग या फिर आवासीय टावरों के पूरा होने पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आवेदन के वक्त करीब 15 एनओसी का होना जरूरी है। इसमें अग्निशमन एनओसी, आर्किटेक्चर, नक्शे की कंपाउंडिंग, प्राधिकरण का बकाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, लिफ्ट व विद्युत सुरक्षा, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जेनरेटर, पर्यावरण क्लीयरेंस की एनओसी जरूरी है। इसके साथ ही सोसायटी में एक निर्धारित अनुपात में इंडब्ल्यूएस व एलआईजी के निर्माण संबंधी एनओसी भी जमा करनी होगी।

सर्टिफिकेट में देरी करने का आरोप लगाते हैं। आरोपों के मद्देनजर जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए सिंगल विंडो पर ही चौक लिस्ट सिस्टम लागू करने का आदेश दिया। इसमें आवेदन के वक्त सभी एनओसी जमा करनी होगी। उसके बाद न्यूनतम 15 में

अधिकतम एक महीने में सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। जीडीए अधिकारियों का तर्क है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए बिल्डर आवेदन करते हैं लेकिन उनमें विभिन्न एनओसी संलग्न नहीं होती हैं। बिल्डरों को नोटिस जारी कर संबंधित एनओसी जमा करने को कहा जाता है।

जिले के सभी डाकघरों में आइपीपीबी की कवायद तेज

गाजियाबाद : इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) को जिले के सभी डाकघरों में शुरू करने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक सभी डाकघर जुड़ जाएंगे। अधिकारियों का कहना है डाकघरों में आइपीपीबी को शुरू करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिले के 282 डाकघर के उपभोक्ताओं को इसका लाभ जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। गाजियाबाद मंडल में डाक विभाग के तीन हेड ऑफिस, तीन सब ऑफिस और नौ ब्रांच ऑफिस में आइपीपीबी के तहत कार्य हो रहा है। इन ऑफिसों में अधिकारियों की तैनाती भी की

गई है। गाजियाबाद के सभी डाकघरों में आइपीपीबी सुविधा मिलने से लोगों का लाभ मिलेगा, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग उपभोक्ताओं को बैंकिंग सुविधा दे सकेगा। उपभोक्ता आइपीपीबी के तहत तीन तरह के रेगुलर, बेसिक और डिजिटल खातों को खोल सकते हैं। इन खातों में जमा राशि पर भी अन्य बैंकों के मुकाबले अच्छा ब्याज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देगी। प्रवर डाक अधीक्षक राम नरेश सीकरिया का कहना है कि जिले के सभी डाकघरों में आइपीपीबी शुरू करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। कुछ डाकखानों में इसका सेटअप भी लगा दिया गया है।

EDITORIAL**Onion price slump sharpens PM? Narendra Modi's election stakes**

Onion prices have a long and layered relationship with Indian politics, having played a role in shaping election results since 1980. Usually governments squirm (and opposition parties rejoice) when the price of the staple is too high for consumers; this time around with a few state poll results due Tuesday and general elections around the corner the problem is the opposite: Prices received by onion farmers are distressingly low. A grower in Maharashtra recently made news when he sent all the money he received for his produce apaltry 1,064 rupees for 750 kilos to the prime minister's charitable fund as a mark of protest. A growing disenchantment with the faltering profitability of farming has emerged as a political variable. But how much of a risk does it pose to the government? One state election where that question may get answered is Madhya Pradesh. This central Indian state, ruled by Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party, has a high dependence on agriculture. This goes beyond rice and wheat, the two cereals that have been the focus of India's food self-sufficiency drive, to include soybean, mustard, cotton, lentils and, of course, onion.

The core of New Delhi's rural support program is so-called minimum support prices, or MSPs—but these aren't paid on every crop or to every farmer. New Delhi, on average, buys 26 percent of the country's annual wheat cultivation and 28 percent of its paddy output for its own granaries, but the figure for mustard is 4 percent and in onion, there are no federal government purchases. State administrations have instead attempted to compensate growers on their own when onion prices collapse and farmer suicides becomes politically embarrassing; but their resources are too limited to make a dent.

Similarly, a government-appointed committee found out that in only 6 percent of India's farmers have gained from selling wheat and paddy directly to a state procurement agency, meaning the vast majority aren't even involved in the MSP system. State procurement of wheat is heavily concentrated in Punjab and Haryana; those two northern states, as well as the southeastern Andhra Pradesh, account for the bulk of government-sponsored rice purchases. For most farmers and most produce, the MSP — and its lofty goal of giving farmers a 50 percent margin on their cost of production — is an empty slogan. Even the Indian central bank got it wrong when it read a significant bump in MSP announced for 14 crops in July as a harbinger of higher inflation post their autumn harvest. The program doesn't cover enough of the market to have such a dramatic effect. With market prices below state-procurement prices by as much as half in some instances, the bigger risk now is of disappointing rural demand. There has to be a better way to make the economies work. The state can't be a purchaser of an ever-expanding set of commodities it can't stock or sell, and politicians can't forever be seeking rural votes by promising fiscally expensive debt waivers. Opposition leader Rahul Gandhi has promised to waive loans of farmers in arid northwestern Rajasthan a state exit polls suggest his Congress Party may wrest from Modi's BJP in Tuesday's count within 10 days of forming government. He has made similar promises to voters in Madhya Pradesh, and its neighboring state of Chhattisgarh.

-By Dr. Dheeraj Kumar Bhargava

Hospital cleaning staffer starts hunger strike over pay

NOIDA: Failing to get their concerns heard despite a seven-day long strike, one of the housekeeping staffers at the district hospital has started a hunger strike, causing chaos at the facility. Anokhi Lal (45), who is one of the oldest staff members, has decided to spearhead their mission and said he would fast unto death. "I have been working at the district hospital for the past eight years. I have four children and two of them are studying. One of my daughters has started working at a beauty parlour due to our financial condition.

The other is not studying. How can we feed our children with a salary of merely Rs 6,000?" he said. The monthly salary of the housekeeping staff, who were getting about Rs 12,700, was reduced to Rs 7,613. A chaos followed at the hospital when the workers on strike tried to stop the workers from the Super Speciality Paediatric Hospital & Post Graduate Teaching Institute (SSPHPGTI) from cleaning the hospital on Thursday morning. As the protest intensified, the authorities of the district hospital called police.

Three more air quality machines to ready by January

NOIDA: The Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) will start installing three new ambient air-quality monitoring machines in Noida and Greater Noida from Monday. This will take the total number of such machines to six. The installation of these machines, which have been imported in parts, is likely to be over by the end of December and readings will start in January. These will be installed at Balak Inter College near Greater Noida West, at the UPPCB office at Sector 1 and on a Noida Authority plot in Sector 116 to cover the 7x sectors. "The location at Sector 116 has been chosen to cover the 7x sectors, where new apartments have come up recently.

Jumping signal: 900 in Noida to lose licence for three months

NOIDA: Traffic police have recommended suspending for three months the driving licences of 900 Noida residents for jumping signals. All these traffic offences were recorded in August and September this year. Of these 900, the transport department issued notices to 638 violators on Friday, giving them a week's time to hand over their licences. The others had been issued notices before that. Should the notices be ignored, parking attendants and traffic cops will be authorised to seize these vehicles both registration number and the violator's name are on the list if they are spotted. The list will be shared with parking personnel too, officials said. "Under the guidelines of the Supreme

RWAs to test sanitation, upkeep plan

NOIDA: In a pilot project, 10 sectors have been shortlisted by the Federation of Noida Residents Welfare Associations (FONRWA) to carry out horticulture and sanitation work for a trial period of three months. Under the project, one set of five sectors (35, 20, 11, 34 and 51) will carry out all horticulture-related work, while a second set of sectors (47, 49, 51-C, D and F blocks), 52 and sector 66) will undertake the job of sanitation upkeep. In each of these sectors, the RWA federation has offered to carry out the job by charging 75% of the cost of what the Authority currently pays to private contractors.



Court committee on road safety, names of violators involved jumping a traffic signal have been shared with the department. The committee has directed that licences can be suspended in case a commuter indulges in violations like jumping a signal, drunken driving, speeding and wrong-side driving," SP (traffic) Anil Jha said. ARTO (enforcement) Himesh Tiwari said that he had received the list and the department would suspend the licences for three months.

Final inspection for Aqua Line nod as it eyes Xmas launch

NOIDA: The commissioner of metro rail safety (CMRS) will inspect the 29.7km Aqua Line from December 11 to 13 for the final certification needed to start commercial operations on the corridor that is likely to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on Christmas day. The Noida Metro Rail Corporation (NMRC) has been expecting an inspection by CMRS S K Pathak for the past

one month. The final inspection includes exhaustive checks and re-checks on different public safety mechanisms, including security system, alarms, emergency stops, and entries and exits at all 21 stations of the corridor. Earlier, in the first phase of the checks, the deputy CMRS had conducted a full trial of the metro line along with a two-day test of the rakes that will run along the entire corridor.

UPI app user loses Rs 6.8 lakh from his bank account

NOIDA: A resident of Sector 12 has alleged that he was cheated of Rs 6.80 lakh through the UPI app. A complaint has been lodged at Sector 20 police station that has been referred to the cyber cell. According to 30-year-old Mohan Lal, the amount was transferred from his SBI savings account through the UPI app by hackers in the past two months.

Stuck at the gates, waiting for funds: Why Ghaziabad metro won't start in December

GHAZIABAD: The Dilshad Garden-New Bus Stand metro route is unlikely to start functioning before January or February 2019 because of several roadblocks that the Delhi Metro Rail Corporation is facing, prime among them is an approval to the project from the Union cabinet that will pave the way for the Centre's share of Rs 329 crore. The route was earlier expected to be flagged off on December 25. Work on it gained momentum after the UP government sought to know from the Ghaziabad Development Authority (GDA) the progress of work



and vice-chairperson Kanchan Verma assured them the project would be completed by the end of this month. TBC visited the New Bus Stand station and spoke to officials on how the work was progressing on the ground. "Work on the ticket counter is well in place while escalators and lifts have been installed. The foot overbridge, too, is being installed," an official said.

Tree-felling permitted, residents step in, stop it

NOIDA: Residents of Sector 137 stopped workers of the Noida Authority from cutting down two neem and a sheesham tree that are obstructing traffic. However, four neem trees had already been felled by the time the residents raised the objection. The workers had permission from the forest department to cut seven trees in total. The Authority said they had decided to remove the trees after repeated complaints that they stood in the middle of the road and had caused a number of accidents. The residents said that cutting the trees was not the solution.

Relatives raid police station in Ghaziabad, free 22-year-old held for harassing woman

GHAZIABAD: Relatives of a 22-year-old man, who was jailed for allegedly harassing a woman, barged into Tronica City police station late on Monday night and freed him after the cops on duty did not allow them to offer the accused fish and liquor. The dozen-odd relatives of Rahul, a resident of Khyala in Delhi, also thrashed a constable with rods and sticks, broke furniture, ransacked the police station and fled before reinforcements could arrive. Till Wednesday evening, seven persons had been arrested for the ruckus. Rahul, whom his relatives had freed, is untraceable. Devi Pal, the

constable hit with rods and sticks, suffered injuries to the head and upper part of the body. He said he had picked up a wireless set to call for additional force but the attackers broke it before pouncing on him. Police said Rahul had come to Ghaziabad on Monday evening to meet a friend near Signature City. He was picked up by a police patrol van after a woman accused him of harassing her and brought to Tronica City police station before midnight. Rahul had also threatened relatives of the woman with dire consequences when they opposed his lewd comments.

Police fail to trace girl, villagers protest

Noida: People of a Greater Noida village surrounded the Dadri police station on Saturday after a body was found in the village lake. On Wednesday, a 17-year-old girl had left her house for tuition classes, but had been missing since. The family had lodged a complaint at Dadri police station on December 6. The family of the girl have accused police of inaction in tracing her. "We got to know that a girl's body was found in a lake in Khatna. This enraged the locals and we reached the Dadri police station," said Raman, one of the protesters.

Broker found dead near Crossings police outpost

GHAZIABAD: A 28-year-old property dealer was found dead with a bullet injury on the forehead behind a bush 200 metres from the police outpost at Crossings Republik. The deceased, Ashwani Sharma, was a resident of Chipiyana and ran an office in the same locality along with his younger brother Mohit (25). One of Ashwani's friends said that he had called him up under the influence of alcohol on Thursday night and told him he would commit suicide. Police, too, said preliminary investigation pointed to a suicide. Ashwani's family, however, refused to buy the argument,



pointing out that there were a few glasses and a liquor bottle in his car that was parked at some distance. The property dealer's wallet and his mobile phone were also found at the spot, which potentially rules out any attempt at robbery. Ashwani's uncle Ramesh Sharma alleged murder and raised a few questions for the police. "It is surely a case of murder, but the perpetrators

Noida to use NSA to deny call centre cons bail

Noida: The district administration is planning to charge operators of fake call centres in Noida under provisions of the National Security Act. Sham call centres have mushroomed in the city over the past few months and spread their tentacles in the US and European countries. District magistrate BN Singh made the announcement on the sidelines of a news conference held to inform that the NSA had been slapped against Anil Bhati, a member of the Sundar Bhati gang, for allegedly plotting the murder of BJP leader Shiv Kumar Yadav and his two

guards. He said the repeated incidents of call centres getting busted in Noida was "tarnishing the image of the country". "The district administration is taking strict action against them (operators of fake call centres). We are planning to charge them under the NSA," Singh said. Charges under NSA mean the accused will not be able to apply for bail. The menace of fake call centres in Noida has assumed such massive proportions that a team from the FBI and Canadian police flew down to the city and appealed to SSP Ajay Pal Sharma to rein them in.

Can all Noida homes have independent meters in 3 months? It's a tough road

Noida: The state government's decision to provide electricity connection to a flat owner directly in an apartment complex may have brought relief to lakhs of residents of highrise societies in the twin cities, but the UPERC March 31 deadline poses a major challenge to the power discom that faces a mammoth task for conversion from single to multi-point connections. There are about 250 residential projects in Noida and 204 in Greater Noida and GNoida (west).

GDA says 95% of road repairs are complete. This is what it looks like

Ghaziabad: Stretches of roads across several parts of Ghaziabad, including Indirapuram and Raj Nagar, are riddled with potholes even though the Ghaziabad Development Authority (GDA) claims to have repaired 95% of these stretches. The GDA had recently carried out drive to make 160km of roads under its jurisdiction "pothole-free". "We had embarked on this drive over the past few months. We have restored a number of uneven roads and even built one. In total, we have either repaired or laid 160km of roads in the city. This



includes 26 stretches of 67km in Indirapuram and 41km in Madhuban-Bapudham. The city now has over 95% of pothole-free roads," said VN Singh, chief engineer at the GDA. A drive down Mangal Bazar Chowk in Indirapuram, however, tells a different tale. In Nyay Khand and Shakti Khand, some stretches are filled with craters.

Grades, e-courts and conciliation forums on UP-RERA’s to-do list

GHAZIABAD: The Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP-RERA) which came into effect in the state last year is evolving itself to suit to needs of home buyers and promoters alike. In Ghaziabad Development Authority’s awareness workshop on RERA which was held on Saturday, UP-RERA secretary Abrar Ahmed gave a glimpse of what RERA will offer in days to come. In the workshop which was attended by home buyers and promoter’s representatives, Abrar sought to bring clarity on RERA and said that it is committed to protect the interest of home



buyers in the state. In its effort to add more teeth to RERA Abrar said that authority is in the process of introducing grading system of promoters and their projects. “Based on the kind of work done by any promoters we will award grades to their projects so that a prospective home buyer will have a before hand

knowledge of the reputation of the promoters, that way the will have the advantage of choosing projects and promoters with good grades” said Abrar Ahmed, secretary, UP-RERA. The grading will be primarily based on feedback of people who ave been associated with the project and how compliant they the projects and promoters are with the RERA rules. Ahmed also said that e-courts will be instituted for redresal of home buyers complaints and for that a mobile application will be introduced shortly. “There have been instances when it becomes very difficult to track individual cases/complaints

registered with RERA, so a mobile App will be introduced shortly so that complainants could track the status of case without bothering to visit RERA office” said Abrar. The secretary also informed till date there are about 9000 complaints registered with RERA and out of which only 2500 have been disposed. “Given the magnitude of complaints we are faced with the problem of timely disposition of cases so we are instituting conciliation forums across states which will take care of cases which could be solved amicably, this way it will take some of the loads off our back” said Ahmed.

SC: Amrapali promoters, top officials should be prosecuted

NEW DELHI: Tightening the noose around the promoters, directors, statutory auditor and chief financial officer of the Amrapali Group, the Supreme Court on Wednesday said they should be prosecuted for criminal breach of trust and cheating thousands of homebuyers and sought their response. A bench of Justices Arun Mishra and U U Lalit said diverting hard earned money of homebuyers for expanding the business of the Group and for personal benefits of company’s officials amounts to criminal breach of trust and directed them to file response on why they should

not be prosecuted for the offence. The court said the company was not permitted to divert homebuyers’ money for purposes other than building the housing projects for them and even temporary diversion of funds amounts to criminal breach of trust as held in the Harshad Mehta case. It said the company is allowed to invest the profits earned after completing the housing projects to purchase properties but it cannot use homebuyers’ money for the purpose. “The money can be used only for construction of housing projects, How can you use it for purchasing shares.

Rename Ghaziabad Agrasen Nagar: MP to Yogi Adityanath

Ghaziabad: Following the UP government’s approval to change the name of Allahabad to Prayagraj, BJP Rajya Sabha MP Anil Agarwal has written to chief minister demanding that Ghaziabad be renamed Maharaja Agrasen Nagar. The demand to rename Ghaziabad has been raised at a time when Yogi has ruffled feathers demanding a name change for Hyderabad. Speaking at a rally in Hyderabad on December 2, the CM had proposed that the BJP would rename Hyderabad to Bhagya Nagar if elected

to power in the state. “Ghaziabad had been named after Ghazi-ud-din, who had Mughal connections. However, in the past few decades, Agarwals have become numerically significant in Ghaziabad. So, we have therefore demanded that Ghaziabad be henceforth named after Maharaj Agrasen who is the founding father of the Vaishya Samaj,” Agarwal, who wrote to Yogi on Nov 29, said. The district was carved out of Meerut on November 14, 1976.

Paytm plot hatched in a Delhi hotel, cops tell Court

NOIDA: Sonia Dhawan and the other accused in the Paytm extortion case had hatched the conspiracy to blackmail the company’s founder, Vijay Shekhar Sharma, over a series of meetings in a Delhi hotel, police have informed court. It was in a hotel room that Sonia, a former vice-president of Paytm, her husband Rupak Jain and a former Paytm employee Devender Kumar would instruct the fourth accused, Rohit Chomal, on how to make the extortion calls and what to tell Sharma. Rohit, whose arrest has been stayed by the Allahabad high court for lack of evidence, had even



blurted out the names of Sonia and the others during one of his calls, the police told the court. Noida police on Saturday claimed to have provided some incriminating evidence against the accused in a 250-page chargesheet that it submitted in court. “We have charged the accused under

IPC sections 381 (theft by clerk or servant of property in possession of master), 384 (punishment for extortion), 386 (extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt), 420 (cheating and dishonestly inducing delivery of property), 408 (criminal breach of trust by clerk or servant), 120 B (punishment of criminal conspiracy) and Section 66 of the IT Act, 2008,” an officer said. The chargesheet was filed in less than two months. Manoj Pant, the SHO of Sector 20 police station and investigating officer in the case, said their probe had revealed that the accused would talk to

each other over phone and discuss their plan for hours at a stretch. “They would meet at a hotel in Delhi to hatch the conspiracy. We have access to call details of the accused, which reveal that they would also discuss their plan over the phone. During one of the extortion calls, Rohit Chomal had even mentioned the names of Sonia, Rupak and Devender. We have submitted this recording in court. This will act as evidence against Rohit Chomal, whose arrest have been stayed by the court,” he said. “The police have made a strong case against them in court,” he added.

हेल्प लाईन नंबर	
गाजियाबाद प्रशासन	
डीएम -	2824416
आवास -	2820106
एडीएम (सिटी) -	2828411
एडीएम (प्रशासन) -	2827016
सिटी मजिस्ट्रेट -	2827365
आयकर विभाग -	2714144
पासपोर्ट कार्यालय -	2721779
पुलिस अधिकारी	
एसएसपी -	2821120, 2820157
पुलिस अधीक्षक नगर -	2854015
पुलिस अधी. यातायात -	2829520
क्षेत्राधिकारी प्रथम -	2733070
क्षेत्राधिकारी द्वितीय -	2791769
क्षेत्राधिकारी तृतीय -	9958776662
क्षेत्राधिकारी चतुर्थ -	2898131
साहिबाबाद -	2630691
कविनगर -	2711843
लिकरोड -	2770310
इंदिरापुरम -	2275858
लोनी -	2600097
जीडीए	
उपाध्यक्ष जीडीए -	2791114
जीडीए सचिव -	2790891
अस्पताल	
सी.एम.ओ. -	2710754
सी.एम.एस. -	2730038
आपातकालीन -	2850124
कोलम्बिया एशिया -	3989896
यशोदा अस्पताल -	2750001-04
गणेश अस्पताल -	4183900
संतोष अस्पताल -	2741777
सर्वोदय अस्पताल -	2701694
जि0 अस्पताल(एम्बुलेंस) -	2730038
नरेन्द्र मोहन अस्पताल (एम्बुलेंस)	2735253
यशोदा अस्पताल (एम्बुलेंस)	2701695
पुष्पांजली क्रांसले हॉस्पिटल	4188000
पुष्पांजली मेडिकल सेन्टर	43075600
बीएसएनएल	
आदेश कुमार (जीएम) -	2755777
अग्निशमन विभाग	
नगर कन्ट्रोल रूम -	2734906
कन्ट्रोल रूम-कोतवाली -	2732099
जिला कन्ट्रोल रूम -	2766898
पुलिस स्टेशन	
कोतवाली -	2732088
सिहानी गेट -	2791627
कविनगर -	2711843
विजयनगर -	2740797
लिकरोड -	9999993066
इंदिरापुरम -	2902858
साहिबाबाद -	9999993020
लोनी -	2600097
अग्निशमन विभाग -	2732099
रेलवे इन्कवायरी -	9818702101
131	
नगर निगम	
नगरायुक्त -	2790425, 2713580
विद्युत विभाग	
मुख्य अभियंता -	2821025
पूछताछ	
रेलवे कस्टमर -	2797840, 139
रिजर्वेशन -	8888
रोडवेजइन्कवायरी -	2791102

प्रेस विज्ञप्ति ,

समाचार , विज्ञापन

के लिए सम्पर्क करें।

Phone No.:

0120-2850800,

2850297

NBCC, Kotak Investment among 4 shortlisted bidders for Jaypee Infra

NEW DELHI: State-owned NBCC, Kotak Investment, Singapore-based Cube Highways and Suraksha group have been shortlisted as bidders for debt-laden Jaypee Infratech, according to a regulatory filing. Jaypee Infratech is undergoing insolvency proceedings in the NCLT. L&T Infrastructure, which was among the five companies that had submitted expression of interest (EOI), was however excluded from the final list, as per the regulatory filing by Jaypee Infratech. Sources had earlier said that L&T would not be considered for the bidding process as the infrastructure

major was only interested in acquiring the 165-km long Yamuna Expressway that connects Delhi-Noida to Agra. Jaypee Infratech’s interim resolution professional (IRP) Anuj Jain said in the filing that the final list of companies for participating in the Corporate Insolvency Resolution Process of Jaypee Infratech has been prepared as per the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) regulations. Jain had in October started a fresh initiative to revive Jaypee Infratech on the National Company Law Tribunal's (NCLT) direction after lenders rejected an over Rs 7,000 crore bid of Suraksha group.

Noida’s first waste treatment plant inaugurated in Sector 54

NOIDA: A waste remediation plant, claimed to be the first in North-India, was inaugurated in Noida Sector-54 on Sunday. The plant can process 40 ton waste per hour and clear Noida’s 2 lakh ton waste legacy in coming days. Noida Authority CEO Alok Tandon inaugurated the plant and said the facility will solve Noida’s waste management issue. Authority said this will also improve Noida’s Swachh Ranking in 2019. Tamil Nadu based M/S Zigma Global Environ Solutions Pvt Ltd which has a joint venture with South Korean firm – M/S Forcebel Co.

‘NH-24 bypass, Ring Road Xing among busiest junctions’

NEW DELHI: The intersections at NH-24 and Bhairon Marg on Ring Road and the IIT crossing on Aurobindo Marg are the three busiest junctions in south and central Delhi, according to an assessment of traffic flow during morning and evening peak hours. And the big culprit of the congestion are the cars and taxis. The traffic survey of 20 major intersections has brought out that the morning peak hour traffic is maximum around 20,000 passenger car units (PCUs) at NH-24 bypass and Ring Road Crossing. The traffic flow during evening peak hour is about 21,000.



PCU is the common denominator for calculating traffic flow. The survey conducted as part of integrated transit corridor development for Delhi PWD also shows how 57% to 70% share of the peak hour traffic are cars and taxis. It’s no different at IIT crossing on Aurobindo Marg where morning peak traffic is about 19,600 PCUs and 17,600 PCUs at evening. Cars and taxis have

Ghaziabad stops house registry in 321 illegal colonies

GHAZIABAD: Four persons were arrested on Tuesday for allegedly cheating people in the name of getting them loans. The arrests were made on the basis of two FIRs registered at Sihani Gate and Kavi Nagar police stations. In both cases, the accused, two of them working with the sales departments of two leading private banks, assured the victims a loan of Rs 50,000 would be reimbursed in their names after they opened new bank accounts. After the victims gave them their identity and address proof, the accused opened the bank



accounts in their names but did not hand over passbooks and ATM cards to them. Later, on the basis of the bank account and forged salary slips, the accused took two loans of Rs 7 lakh each in the name of the victims. The fraud came to light after the bank called the victims and asked them to deposit the loan EMIs.

Broker death: Cops probe ‘suicide call’ to friend

GHAZIABAD: An FIR under Section 302 (murder) was registered against unidentified persons in connection with the death of a property dealer, whose body was found with a bullet injury to the head near Crossings Republik police outpost on Friday. Police said a forensic team had collected evidence from the spot and further inquiry was being conducted. The deceased, Ashwani Sharma, was a resident of Chipiyana Buzurg and ran an office in the same locality along with his younger brother Mohit (25).

3-year-old drowns in drain outside home in Ghaziabad

GHAZIABAD: A three-year-old boy died after falling into an open drain in Loni’s Khanna Nagar on Monday afternoon. Police said the kid was playing outside his home when he slipped into the drain. He was fished out of the muddy water after his mother raised an alarm. The child was first rushed to a private hospital and then taken to GTB Hospital in Delhi, where he was declared dead on arrival. No police complaint has been filed so far. The deceased, identified as Mohammad Saad, used to live with his father



Salim, an auto-rickshaw driver, mother Afsana, and two elder siblings — Sameer (6) and Aaliya (5). Afsana said she had last seen Saad playing with local kids but could not find him after some time. When she raised an alarm, neighbours searched for the child in nearby areas and found him in the 4ft-deep drain. The boy’s parents refused to get an autopsy done. Umesh Kumar Pandey, the SHO of Loni police station, said an inquiry would be initiated if a complaint was lodged in the matter.

Samajwadi Party leader held for TV studio clash with rival

NOIDA: Samajwadi Party spokesperson Anurag Bhaduria was detained on a complaint filed by BJP’s Gaurav Bhatia in Noida on Saturday after a row that began on the sets of a national Hindi TV news channel debate escalated into a political confrontation. Bhatia lodged a police complaint against Bhaduria for assault. The two were on the same panel during a debate in the afternoon. With Bhaduria being detained for questioning, Samajwadi Party workers surrounded Sector 20 police station, where the complaint was lodged, in the evening in protest.

In GZB, four assault homeguard for stopping vehicle, booked

GHAZIABAD: Four men were booked on Monday for allegedly thrashing a homeguard who had stopped their SUV for checking near Thakurdwara flyover in Ghaziabad. Though the incident took place on Sunday, the FIR was registered on the basis of a mobile phone video clip that was widely circulated on social media a day later. The accused, who are in their mid-20s, have been identified as Atul, Ajay, Nitin and Yogesh. The latter is a resident of Mandawali in Delhi while his friends belong to Etawah district in UP. Police said the

homeguard, Sanjay, who is in his early-50s, had stopped the SUV as it was taking a left turn towards Hapur Road. “Sanjay was on duty at the junction when a wireless message flashed that a Maruti Brezza had rammed a vehicle on GT Road and was speeding in the direction of Thakurdwara temple. Sanjay stopped the vehicle for checking its documents but the men roughed him up in their bid to escape. However, with the help of other cops nearby, the men were taken into custody,” said the SHO of Kotwali police station, Jai Karan Singh.

रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने आर्थिक और सामुदायिक विकास के अंतर्गत बांटे कपड़े व भोजन



BUREAU OFFICE PRATEEK BHARGAVA Bureau Chief

5, Ashok Vihar, 3rd Floor,
GMS Road, Nr. Ballupur
Chowk, Dehradun.
Mobile: +91 8130640011
Email: prateekb@tbcbgzb.com
www.tbcbgzb.com

Contact for Press Release
and Advertisements

BUREAU OFFICE VIKRAM KUMAR Bureau Chief

12/516, Friends Co-operative
Society Vasundhara,
Ghaziabad (UP)
Mobile: +91 8130640077
Email: vikram@tbcbgzb.com
www.tbcbgzb.com

Contact for Press Release
and Advertisements

